

“मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता”—वेलेड फिलिपा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 30 अप्रैल 2026 गुरुवार

सम्पादकीय

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के यक्ष प्रश्न

आज सुचना क्रांति और सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया में गहरे तंज करती डिजिटल सामग्री का उफान है। जो दुनिया की भौगोलिक सीमाओं और सत्ता के शिकड़े से मुक्त होकर स्वतंत्र प्रवाह लिए हुए है। लेकिन इसके बावजूद देश में स्ट्रेडिग कॉमेडियनों और व्यंग्यकारों के लिए राजनेताओं पर व्यंग्य करना तलवार की धार पर चलने जैसा बना हुआ है। नाक पर मक्खी न बैठने देने वाले सत्ताकूट राजनेता कॉमेडियनों पर शिकंजा कसने को तैयार बदे होते हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद के कॉमेडियन शतक उदय के बंगलुरु स्थित स्टूडेंट्स-एज शो में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के संसदीयों के एक समूह ने मंच पर आठवें कोर उद्घाटन मचाया, निरन्तर बदे धूमियापूर्ण भी कहा जाया। टीडीपी के सभकोंको भी मंच पर आकर उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के नारे लगाने को बाध्य किया। इस हुद्दुवन से यह कार्यक्रम बाधित हो गया। इसके चलते न केवल उदय को अपना कार्यक्रम रोकना पड़ा, बल्कि एक बार फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल, दो साल पहले उदय के व्यंग्यवाक्य बुद्धुकूलों के जरिये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबु नायडू और उनके बेटे सयाज मंत्री नारा लोवेश को लक्षित किया गया था। निरन्तर बदे यह अभिव्यक्ति रचनात्मकता पर अंकुश लगाने का कुत्सित प्रयास ही कहा जाएगा। सही मायाना में यह घटनाक्रम हास्य-व्यंग्यपूर्ण असहमति के प्रति बढ़ती अहमशैलीता का एक और उदाहरण है। गाढ़े-गाढ़े विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक वर्गों द्वारा ऐसी अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियाएं सामने आती ही रहती हैं। जबकि हकीकत यह है कि हास्य का संसार बड़े लोगों की सहिष्णुता व सदरता से ही फलता-फूलता है। खासकर इस भारतीय समाज में जहां अक्सर कबीरदास की यह उक्ति दोहरायी जाती है 'यू नन्दिक मरुते राखिए, आंगन कुदो घाला बिना पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुमारे'। उनका कहना था कि आलोकिक चमारी कर्मियां बढाकर हमारे सभावा को सड़ाने और निर्मल बनाने देती हैं। सही मायाना में मर्याद व हास्य हमारे को बहुत अभिव्यक्ति के तौर पर लिया जाना चाहिए।

निश्चित रूप से यह हमारे राजनेता व बड़े लोगों व्यंग्य या आलोचना को सहनता से लेते हैं तो इससे समाज में हास्य-निन्दक मरुप फलता-फूलता है। विशेष रूप से राजनीतिक व्यंग्य भारत में लंबे समय तक सत्ता को आईना दिखाता रहा है। पंडित नेहरु जैसे नेता कार्टूनिस्टों की तल्व अभिव्यक्ति को सहजता से लेते थे और व्यंग्यकारों का सम्मान करते थे। ए पीर-गंभीर राजनेता आलोचना को जनता की नसीहत मानते रहे हैं। कालांतर राजनेताओं की इस सोच में पराभव देखा गया है। विडंबना ही है कि वर्ष 2024 में नायडू व लोकाेश पर किए गए व्यंग्य के लिये उदय को फिर से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को मजबूर किया गया। यह अशोभनीय प्रयास यही दर्शाता है कि वर्य विशेष में असहमति को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उदय प्रकरणी भी इसी दुःखद स्थिति के सिलसिले का हिस्सा है। हाल ही में कॉमेडियन अनुदीप कटिकला और रफीक मोहम्मद को आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन वीडियो के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पर व्यंग्य किया था। वीते साल मार्च में, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के एक होटल में तब तोडफोड़ की थी, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फशद्रोही कहा था। निर्विवाद रूप से यह व्यंग्य-विनोद पर पाबंदी लगायी जाती है और कलाकारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित किया जाता है तो इसका प्रभाव सिर्फ एक शो को ही बाधित नहीं करता। बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों की भी धोका करता है। सही मायाना में यह दिक्कत कहींकभी करने वाला से नहीं है, बल्कि राजनेताओं के अनुसंधानों में है, जो उन पर लोगों का हंसना बर्हास बर्हास नहीं कर पाते। ऐसे में राजनेताओं का नैतिक दायित्व है कि वे लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मर्म को समझें। इसके लिये वे अपने अति-उत्साही सभकों पर लगाम लगाएं। लेकिन विडंबना यह भी है कि पुलिस भी सत्ता की राजनीतिक के अंगे नतमस्कृत नजर आती है। कायरे से उसे भारतीय सचिवालय में वर्णित अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। यहि पुलिस दायित्वों का ईशान्वारी से पालन करती तो उदय जैसे कलाकारों को माफ़ी न मांगनी पड़ती।

जिद की जंग में फंसा होर्मुज

ईरान और अमेरिका के बीच पहले युद्धविराम और फिर शांतिवार्ता की शुरुआत से यह उम्मीद उठी थी कि शियाद हॉर्मुज जलमार्ग से जहाजों से आयाजवाही फिर से सामान्य हो सकेगी। यह मुद्दा सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों के लिए बेहद अहम है। लेकिन हालत एक बार फिर उलझने लगी है। ईजराइल और अमेरिका के सझा हातम के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित कर दिया। तब से अब तक उस रास्ते से केवल चीन और कुछ मिने-चुने देशों के जहाजों के गुजरने की ही खबर है।

ऐसे में भारत समेत कई देशों के लिए यह निराशाजनक स्थिति है। एक तरफ ईरान इस मार्ग को खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए इसका की नाकेद्वी का एलान कर दिया है, जिससे संकट और गहरा गया है। अब ईरान अपनी धरती पर अड्डा है कि जब तक अमेरिका नाकेद्वी नहीं हटाएगा, तब तक मार्ग बंद रहेगा। वहीं अमेरिका भी अपनी जिद पर कायम है कि जब तक ईरान रास्ता नहीं खोलेगा, तब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे।

सवाल यह है कि अरण दोनों यह इसी तरह अड्डे रहें, तो क्या शांति की कोशिशों को किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएंगे? एक ओर स्थिति यह है कि युद्धविराम के बावजूद दोनों देशों में तनाव कम नहीं कर रहे, लेकिन हॉर्मुज जलमार्ग बाधित मनव्यु-पै से तेल और गैस की आपूर्ति अब भी प्रभावित है। इसके कारण कई देशों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, तेल बाजार घट रहे हैं, महाझाई कई देशों में और संसई गैस की कमी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यही इस टकराव की सचसे बड़ी किमत है उदर चुकाने रहे हैं, जो इस संघर्ष का हिस्सा भी नहीं है। या अमेरिका और ईरान को यह लड़ी सोचना चाहिए कि उनके आडियेड रूख के कारण दुनिया की बड़ी आबादी संकट श्रैलने को मजबूर है।

गौरतलब है कि हॉर्मुज जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक समुद्री मार्ग में से एक है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा इसी संकट से गुजरता है। यह इस इलाके में ईरान की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शांति वाता से पहले ईरान ने इस मार्ग को खोलने के संकेत दिए थे, लेकिन युद्धविराम के बावजूद अजवाइल द्वारा लेनाना पर हतबत जारी रहने के बाद उनसे फिर से अजवाइल रोक दी। अमेरिका और ईजराइल ईरान अंतःराष्ट्रीय दबाव बनावने के लियारा से हॉर्मुज को बंद करना समर्थन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जबकि अमेरिका की ओर से लगातार आ रही चेतावनियां हालात को और जटिल बना रही हैं। समाधान कब निकलेगा इसके लिये इंतजार करना होगा।

तपती धारती: कारण और समाधान



-निर्मल रानी-

उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व प. बंगाल जैसे राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन राज्यों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले दिनों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा वीटनेब अवलर्ट भी जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में लू चलने और तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना को लेकर लोगों को सचेत किया है। पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर साल गर्मी के तापमान में इजाफा होता ही जा रहा है। जीवन के लिये एकमात्र इस पृथ्वी तो उम्र के और भी कई कई कारण बढ़ते जा रहे हैं। इन कारणों में खासकर जलवायु परिवर्तन के अलावा हीट डोम और अल नीनो का प्रभाव को रेखांकित किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च दबाव प्रणाली गर्म हवा को जमीन



के पास फंसाकर रइकवन की तरह काम करती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप बजड़, चन्नेमवाद, मिनचण्डर से गर्मी और तीव्र हो जाती है। उधर पहले से ही रहा जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी मिट्टी और कम वनस्पति (वृक्ष कटाव) इसे बढ़ावा देते हैं। इसी को हीट डोम प्रभाव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इसने हीटवेक की तीव्रता और इसकी अवधि दोनों को ही बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि 2026 में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 शहर केवल भारत में हैं। इन गर्म क्षेत्रों में केवल दिन ही नहीं बल्कि रातों की तापमान भी बढ़ी स्वीडियर वर्म नाइट्जर कहते हैं। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। साथ ही इन हीट वेव पर अल नीनो का प्रभाव भी बताया जा

रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2026 में सुपर अल नीनो की आशंका से रिकार्ड गर्मी पड़ना भी संभव है। अल नीनो का प्रभाव ही प्रशांत महासागर में गर्म पानी का दौर हवाओं को कमजोर कर भारत में गर्मी और कम मानसून लाता है। इसी के साथ गर्मी को बढ़ने में अतिप्रति शहरीकरण की भी बड़ी भूमिका है। देश में बरों और खेव व जलवायु नियंत्रण कम होते जा रहे हैं। और शहरीकरण के नाम पर कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। शहरीकरण खर्चने हीट आइलैंड का प्रभाव और कंक्रीट-आधारित विकास इसके लिए खासकर जिम्मेदार है। यह कंक्रीट के जंगल दिन में गर्मी को सोखते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं। उधर शहरों में हॉटो जा रही पैदल-चौकी की कमी से वातावरण में भी घटती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली व अहमदाबाद जैसे

महानगरों में रातें पूरी की तुलना में 60: अधिक गर्म होने लगी हैं। शहरों में कंक्रीट, अडार और सीमेंट की पक्की इमारतें सूर्य की गर्मी सोख लेती हैं तथा रात में धीरे-धीरे छोड़ती हैं, जिससे तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से 5-10 डिग्री अधिक रहता है। बड़े-पैदल-चौकी और हरियाली की कमी से वाष्पीकरण घटता है, जो प्राकृतिक शीतलन प्रदान करता। साथ ही वाहनों, एसी और उद्योगों से निकलने वाली गर्मी इसे और भी तीव्र बनाती है। गोया भारतीय शहरों में बढ़ता शहरीकरण बढ़ते तापमान के लिये 60: तक जिम्मेदार है। और यही तापमान युद्धि प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करता है। शहरीकरण ने गर्मी में 90: इजाफा किया है तथा रात्रिकालीन सहन तापमान लगभग 70-80: तक बढ़ा है। मिसाल के तौर पर जमशेदपुर में शहरीकरण ने तापमान वृद्धि में

100: योगदान दिया। ऐसे में सबसे ज्वलंत प्रश्न यही है कि अंतरिक्ष तापमान वृद्धि की जिम्मेदार हमारी वर्तमान पीढ़ी क्या अपनी आने वाली नस्लों को भी ऐसी ही या इससे भी अधिक तपती पृथ्वी देकर जायेगी या इससे बचने के कुछ उपाय करना चाहेगी? इसके लिये सबसे पहले भारतीय शहरों में हरित आवरण को विस्तार देने की संकल्प जरूरत है। हालांकि इसके लिये अनेक सरकारी योजनाएं व स्थानीय उपाय प्रभावी है जोकि शहरी गर्मी बच करने में हमारी सहायता करेगा है। इसके लिये वाक्यावृत्त कार्य योजना बनाकर तथा वर्षात्रुतु को आरम में ही सरकारी और गार निष्ठाय भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने जा सकते हैं। कई रास्य इस दिशा में सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। वृक्षारोपण को एक आंदोलन का रूप देने के लिये हर व्यक्ति अपने परिवार के शादी ब्याह, मैरिज एनिसवर्सो, बडेह, जन्म मुजु बरसी जैसे अवसरों को वृक्षारोपण कर इन अवसरों को यादगार बनाने के साथ साथ जलवायु को बेहतर बनाने की दिशा में भी अपना कीमती योगदान दे सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति जहां जमीन कम हो वहां अपने घरों की छतों पर सुरुवा गर्डिनिंग कर सकता है और रोडवेक गार्डन भी लगा सकता है। अपने घरों के खुले क्षेत्रों में अधिक से अधिक गमने लायक भी तापमान को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है तथा ताजी ऑर्गेनिकल प्रोडक्ट्स का सेवती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में यह देशभर में अचानक कोरोना प्रभावित लोगों के लिये ऑर्गेनिकल की कमी पैदा हुई थी उस समय

लोगों को हरियाली और वृक्षारोपण की खूब राय आई थी। कई बीमार लोग तो खेतों में पेड़ों के नीचे वैटकर स्वास्थ्य लाभ लेते देखे गये। इस आपदा ने ऑर्गेनिकल को लेकर लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ायी कि उसी समय से गमलों व पौधों की नर्सरी का व्यवसाय कई गुना बढ़ गया। बहरहाल गमलों में तापमान वृद्धि से बचने व इसके दीर्घकालिक उपाय करने के साथ साथ तात्कालिक रूप से शरीर पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव से बचाव करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को डिहाइड्रेसन से बचाना और शरीर को हाइड्रेटड रखना सबसे जरूरी है। इसके लिये बहुत सारा पानी पीना चाहिए और बार बार पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, सूप व ओएसएल जैसे शीतल थप भी शरीर को तापमान को नियंत्रित रखने में मददगार होते हैं और डिहाइड्रेसन रोक्ते हैं। जीरा, धनिया या खस मिला डंढा पानी भी इसके लिये बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही आवश्यक रूप से बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही घरों में वृद्धि संसाधित आदि लगाकर धूप को रोका जा सकता है। रात के समय डिखिलिया खुली रखने साथ चलने व आवश्यकता हो तो नीले कपडे पहनने या उन्हे पानी में गमले में पेरेंगे तो उन्हे पानी में भिजोरकर रखने से भी प्रबंध हो सकते है राहत पाई जा सकती है। इस मौसम में आहार में भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हल्का व पोषिक भोजन लेना चाहिए। जंक फूड को तो पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहिए। इसकायार से धरती के इस बड़ते तापमान का हम किसी हद तक मुकाबला कर सकते हैं।

आया राम-गया राम की राजनीति और संविधान



-विश्वनाथ सचदेव-

क्या दल-बदल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वह उत्तरदाता की भी विश्वास में लें जिसने उन्हें चुना है? कोई कानून इस आशय का भी बना चाहिए जो मतदाता के 'अधिकार' को संभाल में ले। कुछ ऐसी व्यवस्था भी है, जो यह निश्चित करे कि दल-बदल करने वाले निर्वाचित व्यक्ति को अपने मतदाता से भी पहले पूछना पड़े। लगभग सात साल पुराना किरसा है, जिसे भारतीय राजनीति के संदर्भ में चटखारे ले-लेकर सुना-सुनाया जाता है। हरियाणा विधानसभा के एक विधायक थे गया लाल। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे वे। एक दिन अचानक उन्हें इहलाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी उनके अनुकूल नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। कुछ घंटे बाद उन्हें लगा उनका यह निर्णय सही नहीं है। वे फिर अपने घर यानी कांग्रेस पार्टी में लौट आये। फिर अचानक उनके ज्ञान-बहुत खुल गये, उन्हें समझ आया कि उनका सर्वे वाला निर्णय ही सही था। वे कांग्रेस से फिर जुड़ पाते थे बले गये। एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदलकर इन विधायकों ने भारतीय राजनीति के एक नया मंत्र भी दे दिया और यह भी समझा दिया कि जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। वे अपने अपने साथी या मतदाता को तैयार नहीं थे कि किसी राजनेता को जनता की सेवा के लिए पार्टी बदलनी जरूरी लग सकती है। वे यह मानते थे कि इस तरह के निर्णय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते नेता लोग तो पण्डित नूनन काम नऊ कि रणनीति की नाम पर देश की राजनीति को एक नम मिला गया-आया राम, गया राम!

साठ साल पहले शुरू हुई राजनीतिक स्वार्थों की यह प्रवृत्ति तब एक अपवाद थी, अब यह जैसे आम



वात है। नवीनान उदाहरण कल तक आम आदमी पार्टी के प्रखर नेता कहलाने वाले संसद राघव चड्ढा का है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे राघव चड्ढा। पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके थे वे। पार्टी के कोषाध्यक्ष की संदरभता भी दी। फिर उन्हें ज्ञान-बहुत खुल गया। उन्हें लाल-जित्त भावरेण्य जनता पार्टी को वे 'असहज गुड़ों की पार्टी' मानते थे वह वास्तव में भारतीयों की सही सेवा करने वाली पार्टी है और उन्होंने घोषणा कर दी कि वह आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का पदनाम धारण रहे हैं। यह इहलाम अलेखे राघव चड्ढा को ही नहीं हुआ, वे अपने साथ आम आदमी पार्टी के छह संसद के भी ले गये। राज्यसभा के सभापति ने बिना कुछ पूछे ही रूप में भाजपा के सदस्य के रूप में मर्यादा भी दी दे ही। राघव चड्ढा की पुरानी पार्टी यदि चाहे तो वह अपने सदस्यों को इस किरवाई और भाजपा में उनके परिवार को चुनौती दे सकती हैं। पर दल-बदलुओं का अवतरक का इतिहास तो यही बताता है कि घने ही उच्चतम व्ययालय दल-बदल में इस प्रक्रिया को संभालिका पाप की संज्ञा दे दे, पर इन कलिक पापियों को कोई संज्ञा मिलती नहीं!

'दलबदलुओं को सजा देने की कोशिशों में एक कोशिश दल-बदल के खिलाफ कानून बनाना भी था, यह 1985 में देश की संसद में एक संशोधन प्रस्ताव का रूप ले-बदल की रणनीति इस लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कदम उठाये गये। तब हुआ कि पार्टी के दो तिहाई सदस्य निर्णय यदि किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तभी इसे 'दिलना यात्रा जायेगा, अन्धरा एसका करने वाले नती की संदरभता बनाने मानी जायेगी। पर पेच यह रह गया कि दो-तिहाई संख्या पार्टी की वह संदीयरी दल को? इसमें एक गाड यह नहीं है कि विलय का निर्णय सदस्यों को अपने साथ जुडने के लिए बाध्य करता है। इतका मतलब यह है कि सदस्य

एक देश, एक पाठ्यक्रम: संधीयता का संकट या शिक्षा क्रांति?



-डा. सत्यवान सोरम-

जब चाहे सत्ताकूट पार्टी का 'आया राम' बन सकता है। सवाल यह उठता है कि कोई आया राम या गया राम क्यों अपनी मूल पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है? क्या सचमुच यह कोई नीतिगत निर्णय होता है या फिर इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ होते हैं?

भारत के दल-बदलुओं का इतिहास बताता है कि लगाग शत प्रतिशत राजनीतिक स्वार्थ होता है। अक्सर इस आशय के आरोप भी लगते हैं कि अपने अपराधों के पाप बोधे, या फिर सत्ताकूट दल के लितों को दृष्टि में रखकर भी 'आयागम' गुणनाम का यह खेल होता है। यह खेल खेलेने वालों की आधिकारिक संख्या बतानी तो मुश्किल है, पर ज्ञात तथ्यों के अनुसार 1985 में दल-बदल विरोधी कानून लागू होने के बाद से अब तक संकेदों संसद और विधायक दल-बदल चुके हैं। कहते हैं कानून बनने से पहले 1967 से 1971 के बीच लगभग 50 प्रतिशत विधायकों ने अपनी पार्टी बदली थी, बड़े आकार, गयाराम की राजनीति क्रांति हुआ।

मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं अनुसूची के तहत कम से कम सात प्रमुख अवसरों पर सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। सन 2022 में हमरा महाप्राध और गोमा में दल-बदल का यह 'खेला' देखा, इसके दो साल पहले मणिपुर के तीन विधायकों को अन्याय उद्धार में पानी था और अब आम आदमी पार्टी का मामला बन रहा है। निर्णित रूप से यह धार मानें इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी राजनीति में संकटों और नीतियों के लिए जंगल लगातार कम होती जा रही हैं। कमी विधायक या संसद अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एस कदम उठाते हैं और कमी राजनीतिक दल (पड़ि सत्ताकूट क्रांति) अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे दलों के सदस्यों को अपने साथ जुडने के लिए बाध्य करता है।



"रकने वालों का इतिहास नहीं होता। एक देशदूक पाठ्यक्रम शिक्षा के नाम पर लूट का विरोध जारी रहना चाहिए।" यह वाक्य आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चल रहे सबसे बड़े विमर्श को सटीक रूप से सामने रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एम्पे) 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित नीति है।

भारत के दल-बदलुओं का इतिहास बताता है कि लगाग शत प्रतिशत राजनीतिक स्वार्थ होता है। अक्सर इस आशय के आरोप भी लगते हैं कि अपने अपराधों के पाप बोधे, या फिर सत्ताकूट दल के लितों को दृष्टि में रखकर भी 'आयागम' गुणनाम का यह खेल होता है। यह खेल खेलेने वालों की आधिकारिक संख्या बतानी तो मुश्किल है, पर ज्ञात तथ्यों के अनुसार 1985 में दल-बदल विरोधी कानून लागू होने के बाद से अब तक संकेदों संसद और विधायक दल-बदल चुके हैं। कहते हैं कानून बनने से पहले 1967 से 1971 के बीच लगभग 50 प्रतिशत विधायकों ने अपनी पार्टी बदली थी, बड़े आकार, गयाराम की राजनीति क्रांति हुआ।

मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं अनुसूची के तहत कम से कम सात प्रमुख अवसरों पर सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। सन 2022 में हमरा महाप्राध और गोमा में दल-बदल का यह 'खेला' देखा, इसके दो साल पहले मणिपुर के तीन विधायकों को अन्याय उद्धार में पानी था और अब आम आदमी पार्टी का मामला बन रहा है। निर्णित रूप से यह धार मानें इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी राजनीति में संकटों और नीतियों के लिए जंगल लगातार कम होती जा रही हैं। कमी विधायक या संसद अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एस कदम उठाते हैं और कमी राजनीतिक दल (पड़ि सत्ताकूट क्रांति) अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे दलों के सदस्यों को अपने साथ जुडने के लिए बाध्य करता है।



राज्य अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आंतरिकताओं के अनुसार संशोधन कर सकें। लेकिन विशेष करने वाले रास्यों का मानना है कि यह लचीलापन केवल प्रतीकात्मक है और अपने में यह एक केंद्रीकृत पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास है।

संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात् फेडरल और रास्य दोनों की इस्मे भूमिका है। ऐसे में रास्यों का आस्य है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओंकृतिते समग्र शिक्षा अभियानकृतिते महिले बाल केंद्र को रोककर दबाव बन रहे हैं। तमिलनाडु इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां हजारों करीब रूपये की राशि रोकी गई। राज्य सरकार ने इसे अपनी नीतिगत स्वतंत्रता हमला बताते हुए इसका विरोध किया।

इस विवाद का एक बड़ा पल्लू भाजपा और सांस्कृतिक पहलवान से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्य हिंदी को 'अपने जाते वाली भाषा' के रूप में देखते हैं। जबकि केंद्र का कहना है कि हिं-भाषा पूर के मंत्रिणी एक भाषा को अनिर्वाय नहीं किया गया है। इसके बावजूद यह आशंका नहीं हुई है कि एक समान पाठ्यक्रम से क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की उपेक्षा होगी। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की सभूद सांस्कृतिक विरासत या बंगाल का साहित्यिक योगदान एक मानकीकृत पाठ्यक्रम में सीमित हो सकता है।

केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नीति शिक्षा में असमानताओं को कम करेगी। वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी अंतर दिखाई देता है। केंद्र द्वारा एक ओर नीति रचले तो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, वहीं सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण परिणाम कमजोर रहते हैं। एक देश, एक पाठ्यक्रम के माध्यम से एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश के हर बच्चे तक लचीलापन दिया गया है ताकि

को समान अवसर मिल सकें। इसके साथ ही, यह नीति कोला-आधारित शिक्षा पर जोर देती है, जोकिडि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसे विषयों को प्रारंभिक स्तर से जोड़ने का प्रस्ताव है, जो बाल्य की जरूरतों को ध्यान में रखता है। यह पहल भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हालांकि आलोचक इसे 'शिक्षा के नाम पर लूट' भी करार देते हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा और केंद्रिय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कोटा जैसे शहरों में पहले से ही कॉलेज का बड़ा बाजार है, और एक समान परीक्षा प्रणाली (जैसे एम्पे) इसे और महत्वपूर्ण बनाएगी और सरकारी स्कूलों को कम कर सकती है। वहीं, केंद्र का मानना है कि एकीकृत प्रवेश परीक्षा परदेसिता बढ़ाएगी और श्रेष्ठता के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्य हिंदी को 'अपने जाते वाली भाषा' के रूप में देखते हैं। जबकि केंद्र का कहना है कि हिं-भाषा पूर के मंत्रिणी एक भाषा को अनिर्वाय नहीं किया गया है। इसके बावजूद यह आशंका नहीं हुई है कि एक समान पाठ्यक्रम से क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की उपेक्षा होगी। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की सभूद सांस्कृतिक विरासत या बंगाल का साहित्यिक योगदान एक मानकीकृत पाठ्यक्रम में सीमित हो सकता है।

केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नीति शिक्षा में असमानताओं को कम करेगी। वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी अंतर दिखाई देता है। केंद्र द्वारा एक ओर नीति रचले तो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, वहीं सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण परिणाम कमजोर रहते हैं। एक देश, एक पाठ्यक्रम के माध्यम से एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश के हर बच्चे तक लचीलापन दिया गया है ताकि

